(d) It is expected to add 1174.30 MW of new capacity in the Eastern Region during 1995-96. The tentative programme for the terminal year of the 8th Plan i.e. 1996-97 is for an addition of 973 MW capacity. Various other measures taken to improve the availability of power in the Eastern Region include expediting commissioning of new generating capacity, improving the performance of existing capacity, reduction in transmission and distribution losses, implementation of demand management and energy conservation measures etc.

Excise Collection

93. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have made any review of the performance of different States and also the Central Government on excise collection; and

(b) if so, the State-wise and Central Government's achievement thereon during the years 1994-95 and 1995-96?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) and (b) Data regarding revenue collection from Union Excise duties is not maintained State-wise. Therefore, even though revenue receipts from Union Excises are monitored on a continuing basis, no review thereof on the basis of State-wise performance is made.

Figures of revenue collections from Union Excise duties, exclusive of cesses which are not administered by the revenue Department, are given below for 1994-95 and April 1995 to January 1996:

Year	Revenue (Rs. in crore)
1994-95 (P)	37466.55
1995-96 (P) (UptoJan '96)	32393.48

P-Provisiortal.

बिजली की दरों में वृद्धि

94. **श्रीमती सुषमा स्वराज** :

श्री राम जेठमलानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 फरवरी, 1996 के दैनिक "टाइम्स आफॅ इंडिया" में "साल्वे स्ट्रेसिस नीड टू हाइक पावर टेरिफ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार देश में बिजली की दरों में वृद्धि करने को आवश्यक समझती है,

(ग) यदि हां,तो क्या यह भी सच है कि देश में कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली बिजली की दर उसकी उत्पादन लागत से कम है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में कल कितनी प्रतिशत बिजली कृषि क्षेत्र में औसतन उपयोग हो रही है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। जनवरी, 1993 में आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में अपनाई गई काग्र-योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया था कि उत्पादन और आपूर्ति की बढ़ी हुई लागत को मद्देनजर रखते हुए सभी टैरिफों को आवधिक रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।

(ग) जी, हां।

(घ) अखिल भारत आधार पर वर्ष 1993-94 में कृषि क्षेत्र को बेची गई विद्युत की प्रति यूनिट औसतन वसूली 17.847 पैसे/यूनिट थी, जबकि आपूर्ति की औसत लागत 154.75 पैसे/यूनिट थी। जनवरी, 1993 में आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में पहले ही यह निर्णय ले लिया गया था कि कृषि टैरिफ को कम से कम 50 पैसे /कि.वा.आ. तक बढ़ा दिया जाना चाहिए । कुल बेची गई यूनिटों में से लगभग 30 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को आपूर्ति की गई थी।

बिजलीघरों में संकट

95. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** :

श्री अनन्तराय जायसवाल :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

f(क) क्या यह सच है कि देश के अनेक बिजलीघरों में विद्युत संकट पैदा हो गया है,

(ख) यदि हां, तो ऐसे बिजलीघरों की संख्या कितनी है, वे किन-किन राज्यों में स्थित है तथा इसके फलस्वरूप राज्यों को कितनी हानि हुई है,

(ग) देश भर में बिजली की मांग वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 में क्या रही तथा पिछले दो वर्षों की तुलना में वर्ष 1995-96 में बिजली की मांग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और

(घ) सरकार ने राज्यों द्वारा बिजली की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए अब तक क्या-क्या कदम उठाए हैं और उनके क्या परिणाम निकले ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल) : (क) और (ख) अप्रैल, 95-जनवरी, 96 की अवधि के दौरान देश में समग्र लक्ष्य की तुलना में 0.9% अधिक रहा है । तथापि, कुछ विद्युत केन्द्रों में इस अवधि के दौरान लक्ष्य की तुलना में कम विद्युत उत्पादन हुआ है जैसा कि अनुपत्र में विवरण दिया गया है । [देखिए परिशिष्ट 176, अनुपत्र सं.4]

(ग) 1993-94 से 1995-96 की अवधि के दौरान पूववर्ती वर्ष की तुलना में ऊर्जा आवश्कयता और प्रतिशतता वृद्धि नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार है ।

वर्ष	आवश्यकता (मि.यू.)	प्रतिशत वृद्धि
1993-94	3232525	5.9
1994-95	352260	9.0
1995-96	378200 (प्रत्याशित)	7.4

(घ) विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए गए उपायों में अधिष्ठातिप क्षमता का उच्चतर समुपयोजन, ताप विद्युत की आपूर्ति का मानीटरिंग करना और विद्यमान विद्युत केन्द्रों का आधुनिकीकरण एंव उन्नयीकरण किया जाना शामिल है । इसके अलावा पारेषण एंव वितरण हानियों को कम करने के लिए स्कीमें आरंभ करना, केन्द्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर सार्वजनिक क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं के तीव्र क्रियान्वयन हेतु भी कदम उठाए गए हैं । निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

Black Money

96. SHRI OP. KOHLI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-items titled "I-T deptt. to plug loop-holes in tax system". "Parliament panel frowns on the regime as black money exceeds GDP" and "Government questions Rs. 3,00,000 cr. estimate of parallel economy" appearing in the " Economic Times" and the 'Indian Express' dated 11th January and 7th and 12 July, 1995 respectively;

(b) if so, the facts thereof;

(c) the reaction of Government thereto; and

(d) the action taken by Government to remove the deficiencies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) Yes, Sir.

(b) and (d) Since the relevant report of the Parliament's Standing Committee on Finance referred to in the news item has not been received the questions do not

दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों का निर्माण

97. **श्री रामजी लाल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की बढ़ती जनसंख्या और विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वार देश और विशेष रूप से हिसार के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है,

(ख) गत दो वर्षों के दौरान निर्माणधीन दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों के लिए अब तक कितनी धनाराशि आबंटित की गई है,

(ग) क्या इस धनराशि से इसी वर्ष इन केन्द्रों को चालू किये जाने की संभावना है, और